सेबी

बनाम

सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य

(आई. ए. सं. 101-103)

में

अवमानना याचिका (सी) संख्या 412-413/2012

में

सिविल अपील संख्या 9813 और 9833/2011

और

अवमानना याचिका (ग) सं. 260/2013

में

दीवानी याचिका सं 8643/2012

04 जून, 2014

[टी. एस. ठाकुर और ए. के. सिकरी, जे. जे.]

घोटालों-निवेशक-धोखाधड़ी का मामला-एक कंपनी द्वारा वैकल्पिक पूर्ण रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर-ओ. एफ. सी. डी. के रूप में आम जनता से जमा का निमंत्रण/संग्रह-निवेशक समूह द्वारा शिकायत-कंपनी को इक्विटी शेयर/ओ. एफ. सी. डी. एस. या किसी अन्य प्रतिभूति को सार्वजनिक रूप से पेश नहीं करने या सदस्यता आमंत्रित न करने के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा निर्देश-जमानत में, उच्च न्यायालय कंपनी के प्रवर्तक और निदेशकों को संयुक्त रूप से और गंभीरता से एकत्र की गई राशि को 15

प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने के निर्देश जारी करता है-इसके अनुसार एस. ई. बी. आई., न्यायाधिकरण और इस न्यायालय द्वारा राशि की वापसी के संबंध में पारित आदेशों के साथ-साथ धनवापसी करने के लिए समय अवधि बढ़ाने के संबंध में भी-हालांकि, निर्देशों का पालन न करना कंपनी के खिलाफ अवमानना याचिकाएं 10, 000/- करोड़-शर्त का पालन न करना।पीड़ित, प्रवर्तक रिट याचिका दायर कर रहा है, उस आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके तहत अवमाननाकर्ता न्यायिक हिरासत के लिए प्रतिबद्ध था; और हिरासत से रिहाई की भी मांग कर रहा है-इस अदालत द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया गयाः अवमानकर्ताओं द्वारा एस. ई. बी. आई., उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में देरी करने के लिए अपनाई गई विलंबकारी रणनीति और पर्याप्त अवसरों के बावजूद पारित आदेशों के गैर-अनुपालन को देखते हुए अवमानकर्ताओं को अंतरिम जमानत देने वाले आदेश में निर्धारित शर्तों को संशोधित नहीं किया जा सकता है-समकालीनों को निरंतर हिरासत और निरोध के लिए अतिथि गृह में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है-हालांकि, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश और एस. ई. बी. आई. द्वारा कंपनी द्वारा रखी गई चल और अचल संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगाने के आदेश में संशोधन किया गया है-मुद्दों के महत्व और इस तथ्य को देखते हुए कि इन कार्यवाही में तीन न्यायाधीशों की पीठ के मामले को लागू करने की मांग की गई है, तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजी गई कार्यवाही-बड़ी पीठ को संदर्भित।

‘एस. आई. आर. ई. सी. एल. 'कंपनी और एस. एच. आई. सी. एल.' कंपनी 'ने' वैकल्पिक पूर्ण रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर 'ओ. एफ. सी. डी. के रूप में आम जनता से जमा आमंत्रित/एकत्र किए। पेशेवर निवेशक समूह की एक शिकायत पर, एस. ई. बी. आई. ने पाया कि दोनों कंपनियों द्वारा जारी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के तहत धन जुटाना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं था और कंपनी को अपने इक्विटी शेयर/ओ. एफ. सी. डी.

एस. या किसी अन्य प्रतिभूति की पेशकश नहीं करने के निर्देश जारी किए। उच्च न्यायालय ने उक्त निर्देशों को बरकरार रखा और कंपनी के प्रवर्तक और निदेशकों को संयुक्त रूप से और उनके द्वारा एकत्र की गई राशि को जमा की प्राप्ति की तारीख से इस तरह के पुनर्भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया।एस. ई. बी. आई. ने निर्देश दिया कि कंपनी तब तक धन जुटाने के लिए सुरक्षा बाजार का उपयोग नहीं करेगी जब तक कि भुगतान नहीं किया जाता है।अपील में न्यायाधिकरण ने एस. ई. बी. आई. द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा और कंपनी को निवेशकों से एकत्र की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया।इसके बाद, इस अदालत ने धनवापसी करने की अवधि बढ़ा दी और कंपनी को एस. ई. बी. आई. में राशि जमा करने का निर्देश दिया। कंपनी ने निर्देशों का पालन नहीं किया। इस अदालत के आदेश के अनुसार, कंपनी ने एसईबीआई के पास रू.5120-करोड़ जमा किए, लेकिन शेष राशि का भुगतान करने में विफल रही। इसके बाद एस. ई. बी. आई. ने इस न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानकर्ताओं के खिलाफ अवमानना याचिकाएं दायर कीं। समय-समय पर विभिन्न आदेश पारित किए जाते थे। कंपनी की संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण पर प्रतिबंध हटाने की मांग करने वाली इन अवमानना याचिकाओं में तत्काल आवेदन दायर किए गए थे। अवमानना याचिकाओं में कार्यवाही के दौरान, चूंकि इस न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए प्रवर्तक के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किए गए और बाद में प्रवर्तक सहित तीन अवमानकों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद, चूंकि अवमानकर्ताओं ने जमानत देने पर जोर दिया, इसलिए इस अदालत ने अवमानकर्ताओं को अंतरिम जमानत देते हुए एक सशर्त आदेश पारित किया; शर्त यह थी कि वे रू.10,000/- करोड़ जमा करें। अनुपालन पर, अवमानकर्ताओं को हिरासत से रिहा किया जाना था। हालांकि, उपरोक्त निर्देशों का

पालन करने के बजाय, प्रवर्तक ने आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की और उसे हिरासत से रिहा करने की मांग की। रिट याचिका खारिज कर दी गई।

न्यायालय द्वारा निर्देशों के साथ आई. ए. का निपटान करते हुए,यह अभिनिर्धारित किया गया :

1.1 अवमानकर्ताओं की यह प्रार्थना कि वे राशि जमा करने के संबंध में इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए बैंक जमा और अचल संपत्तियों पर प्रतिबंध आदेशों में छूट चाहते हैं, कोई कठिनाई पैदा नहीं करती है। जहां तक जमानत देने या जेल की शर्तों में ढील देने के अनुरोध का संबंध है, अवमानकर्ताओं को अंतरिम जमानत देने के आदेश में उक्त शर्तों पर संशोधन करने का कोई झुकाव नहीं है। आदेश, उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जिसमें अवमानकर्ता जेल के लिए प्रतिबद्ध हुए और न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि उन्होंने अन्य प्रारंभिक चरणों में विलंबकारी रणनीति अपनाने की कोशिश की है और न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करने से परहेज किया है। वैकल्पिक रूप से, निवेदन किया गया कि कम से कम जो किया जा सकता है वह यह है कि अवमानना करने वालों को तिहाड़ जेल से जेल में रखने के लिए एक अतिथि गृह में स्थानांतरित किया जाए ताकि वे जेल की अवमानना करने में सक्षम हो सकें। निर्णय जो इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए आवश्यक हैं। इस अनुरोध का विरोध एस. ई. बी. आई. के वकील ने किया था, जिनके अनुसार अतीत में कई सुनवाई में बार-बार किए गए इसी तरह के अनुरोधों को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, हालांकि इससे इनकार करने वाला कोई विशिष्ट आदेश दर्ज नहीं किया गया था। [पैरा 17] [1029-ए-जी]

1.2 इस तथ्य के अलावा कि अब की गई प्रार्थना अतीत में की गई इसी तरह

की प्रार्थनाओं की पुनरावृत्ति है, जिसने मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के साथ कोई बर्फ नहीं काटा है, तत्काल मामले में सामान्य पाठ्यक्रम से प्रस्थान करने का कोई कारण नहीं है। पीठ ने अवमानकर्ताओं के आचरण सहित परिचर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित और उचित विचार के बाद एक सशर्त जमानत आदेश पारित किया। आदेश को केवल बहुत ही बाध्यकारी परिस्थितियों में ही संशोधित किया जा सकता है। आवेदकों द्वारा दिया गया एकमात्र कारण यह है कि अवमानकर्ताओं की अंतरिम रिहाई या अतिथि गृह में स्थानांतरण उन्हें संपत्तियों का तेजी से निपटान करने में सक्षम बनाएगा और उन्हें आवश्यक बैंक गारंटी की व्यवस्था करने में सक्षम बनाएगा, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।यह उल्लेखनीय है कि जमा की जाने वाली कुल राशि रु 33000/- से रु 35000/-करोड़ थी। अवमानकर्ताओं को अपनी प्रामाणिकता दिखाने के लिए जमानत की शर्त के रूप में उस राशि के एक तिहाई से कम राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। आखिरकार, जब आदेश के इस हिस्से का पालन किया जाता है और अवमानकर्ताओं को मुक्त कर दिया जाता है, तब भी उन्हें शेष राशि जमा करने की व्यवस्था करनी होगी, जो फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह अवमानकर्ताओं का मामला नहीं है कि वे या उनमें से कोई भी किसी भी चिकित्सा स्थिति से पीड़ित है जो अस्पताल में भर्ती होने या किसी भी बीमारी से उबरने के लिए अनुकूल वातावरण की मांग करता है। यह न्यायालय पहले ही उन लोगों से मिलने की अनुमति देने के निर्देश जारी कर चुका है जिन्हें जेल में अवमानना करने वालों से मिलने की आवश्यकता है। वह व्यवस्था वर्तमान में अपर्याप्त नहीं पाई गई है ताकि किसी भी बदलाव की आवश्यकता हो। इस प्रकार, आदेश के संशोधन के लिए प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है। [पैरा 18,19] [1029-जी-एच; 1030-ए-एफ]

1.3 इस निवेदन में काफी योग्यता है कि कंपनियों के समूह द्वारा चल और अचल संपत्तियों के हस्तांतरण और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाले इस न्यायालय

और एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी प्रतिबंध आदेश का प्रभाव अवमानकर्ताओं को इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने से रोकने का है, जिसमें उन्हें 5,000 करोड़ रुपये की समान राशि के लिए बैंक गारंटी के अलावा 5,000 करोड़ रुपये नकद जमा करने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह सच है कि अवमानकर्ता इस न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के लिए जेल जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्हें उक्त निर्देशों या उन शर्तों का पालन करने के लिए कदम उठाने से कुछ भी नहीं रोकना चाहिए जिनके अधीन उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। अवमानकर्ताओं और उनके द्वारा प्रवर्तित कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के खिलाफ प्रतिबंध का ऐसा करने का सटीक प्रभाव पड़ता है। प्रत्यर्थी कंपनी को अंततः एक पर्याप्त राशि जमा करने की आवश्यकता होती है जो वर्तमान अनुमान के अनुसार रु 30, 000 से 35,000 करोड़ रुपये मूल राशि पर उपार्जित ब्याज सहित ऐसी परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य से कम कीमत पर मूल्यवान संपत्तियों की बिक्री जमाकर्ताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपने अक्षर और भावना में विफल करने के लिए बाध्य है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि वकील के अनुसार, एस. ई. बी. आई. संपत्तियों का मूल्य निर्धारित करने या उनकी बिक्री और हस्तांतरण की प्रक्रिया में असमर्थ है। यह उस पृष्ठभूमि में था कि इस न्यायालय ने वकील को संकेत दिया था। अपीलकर्ताओं ने कहा कि प्रतिबंध आदेशों को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है और प्रत्यर्थी कंपनी को ऐसी संपत्तियों की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो 5,000/- करोड़ रुपये 5.000-इसके अलावा नकद जमा करने के संबंध में इस न्यायालय के अंतरिम जमानत निर्देश का पालन करने के लिए पर्याप्त थे। अपीलार्थी के वकील ने उस अवलोकन के अनुसरण में देश के नौ अलग-अलग शहरों में स्थित संपत्तियों की केवल नौ वस्तुओं को बेचने/स्थानांतरित करने की अनुमति के लिए अपनी प्रार्थना को सीमित कर दिया और बयान में ऐसी संपत्ति के

अनुमानित मूल्य का खुलासा किया। निर्देश पर वकील ने एक बयान दिया कि हालांकि उनके द्वारा दायर ध्यान दें में उन शहरों में स्थित संपत्तियों का विवरण दिए बिना नौ अलग-अलग शहरों के नामों का उल्लेख किया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि ध्यान दें में उल्लिखित संपत्तियों की संख्या केवल नौ है और उससे अधिक नहीं है। [पैरा 20] [1030-एफ-एच; 1031-ए-जी]

1.4 कंपनियों के समूह द्वारा धारित संपत्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, ध्यान दें में उल्लिखित नौ शहरों में स्थित संपत्तियों की नौ वस्तुओं की बिक्री और/या बंधक का हस्तांतरण, अवमानकर्ताओं को इस न्यायालय के 26 मार्च, 2014 के निर्देशों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित आदेशने के लिए बिक्री मूल्य उचित और उचित है, यह स्पष्ट किया जाता है कि संपत्ति की कोई भी वस्तु उस क्षेत्र के लिए निर्धारित संपत्तियों के वृत्त मूल्य से कम मूल्य पर नहीं बेची जाएगी जहां ऐसी संपत्ति स्थित है। [पैरा 21] [1031-जी-एच; 1032-ए-बी]

1.5 लंदन और न्यूयॉर्क में स्थित संपत्तियों के संबंध में, 29 मई, 2014 को पारित एक अंतर्वर्ती आदेश द्वारा अवमानकर्ताओं को उक्त संपत्तियों की बिक्री की अनुमति देने के लिए आवश्यक कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। माँगी गई जानकारी में बैंक ऑफ चाइना से अनुमति/अनुमोदन शामिल है जिसके साथ उक्त संपत्तियाँ गिरवी रखी गई हैं और उक्त बैंक से उधार लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सहारा द्वारा रखे गए शेयर शामिल हैं। सहाराओं को बैंक ऑफ चाइना से उक्त संपत्तियों की पुष्टि के लिए ऋण लेनदेन के लिए बकाया राशि प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था ताकि उक्त संपत्तियों के खिलाफ दायित्व की सीमा की स्पष्ट तस्वीर दी जा सके। यह तथ्य कि तीन परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट बैंक ऑफ चाइना के कहने पर तैयार की गई थी, बैंक ऑफ चाइना द्वारा भी सत्यापित

और पुष्टि की जानी चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि विचाराधीन परिसंपत्तियों की किसी भी बिक्री की अनुमति उस कीमत से कम कीमत पर नहीं दी जा सकती है जिस पर उक्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उन मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया गया है जिन्हें प्रतिष्ठित मूल्यांकनकर्ता कहा जाता है। इसलिए, देश के बाहर परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में निर्देश सूचना प्रस्तुत करने और तथ्यों के सत्यापन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। [पैरा 22] [1032-बी-जी]

1.6 आई. ए. को निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटाया जाता हैः

(i) अवमानकर्ताओं को अंतरिम जमानत देने के आदेश में निर्धारित शर्तों में संशोधन के अनुरोध को खारिज कर दिया जाता है।

(ii) अवमानकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर उनकी रिहाई के लिए इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने तक निरंतर हिरासत और निरोध के लिए एक अतिथि गृह में स्थानांतरित करने की प्रार्थना को खारिज किया।

(iii) इस न्यायालय द्वारा और सहारों द्वारा धारित चल और अचल संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले एस. ई. बी. आई. द्वारा पारित आदेशों में संशोधन किया गया है।

(iv) देश के बाहर स्थित तीन संपत्तियों की बिक्री के लिए, सहारा द्वारा आवश्यक दस्तावेज/जानकारी उपलब्ध कराने के बाद प्रश्न निर्धारित करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।

(v) इन कार्यवाहियों में निर्धारण के लिए आने वाले मुद्दों के महत्व और इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जिसे इन कार्यवाहियों में लागू करने की मांग की गई थी, तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित किया गया था,

इन कार्यवाहियों को तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाता है।

(vi) इन कार्यवाहियों की प्रकृति और इसमें शामिल हितधारकों को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एफ. एस. नरीमन से अनुरोध किया जाता है कि वे न्यायालय मित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करें। [पैरा 23] [1032-एफ-एच; 1033-ए-सी; 1035-ए-ई]

सिविल मूल न्यायनिर्णयः आई.ए. संख्या 101-103

में

अवमानना याचिका (सी) संख्या 412 और 413/2012

में

दीवानी याचिका सं 9813 और 9833/2011

अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 260/2013

में

सिविल अपील संख्या 8643/2012

प्रताप वेणुगोपाल, गौरव नायर, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी और विश्व पाल सिंह, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए।

डॉ. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता, केशव मोहन, गौरव केजरीवाल, जतिन पोर, संदीप बजाज, श्रीमती शाली भसीन माहेश्वरी और गौतम अवस्थी, अधिवक्ता प्रतिवादीओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय, न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर, जे. द्वारा पारित किया गया-

1. सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एस. आई. आर. ई. सी. एल.) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एस. एच. आई. सी. एल.)

(इसके बाद संक्षेप में 'सहारा' के रूप में संदर्भित) आमंत्रित किए गए और दावा किया कि उन्होंने आम जनता से जमा राशि एकत्र की है जिसमें मोची, मजदूर, कारीगर और किसान शामिल हैं जिन्हें 'वैकल्पिक पूर्ण रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर' (ओ. एफ. सी. डी.) के रूप में वर्णित किया गया था।प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, एस. ई. बी.] से प्राप्त एक शिकायत पर पाया गया कि दोनों कंपनियों द्वारा जारी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आर. एच. पी.) दिनांक 13 मार्च, 2008 और 6 टी. एम. अक्टूबर, 2009 के तहत धन जुटाना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं था।एक विज्ञापन के माध्यम से, 24 नवंबर, 2010 के अंतरिम एकपक्षीय आदेश में एस. ई. बी. आई. ने सहारों को निर्देश दिया कि वे अपने इक्विटी शेयरों/ओ. एफ. सी. डी. एस. या किसी अन्य प्रतिभूति को जनता को न दें या आगे के आदेशों के लंबित रहने तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से सदस्यता आमंत्रित न करें।उक्त आदेश से व्यथित होकर सहारास ने बॉम्बे में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उच्च न्यायालय ने न केवल एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी निर्देशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, बल्कि 23 जून, 2011 को एक और आदेश भी पारित किया, जिसमें प्रवर्तक श्री सुब्रत राय सहारा और निदेशकों सुश्री वंदना भार्गव, श्री रविशंकर दुबे और सहारा के श्री अशोक रॉय चौधरी को संयुक्त रूप से और उनके द्वारा जारी आर. एच. पी. के सहारास मध्यस्थों द्वारा एकत्र की गई राशि को जमा की प्राप्ति की तारीख से इस तरह के पुनर्भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया गया। इसके अनुसार, एस. ई. बी. आई. ने आदेश दिया कि राशि की वापसी केवल "डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर" द्वारा से नकद में की जाएगी। एस. ई. बी. आई. ने एक निर्देश सहित आगे के निर्देश जारी किए कि सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे पहले एस. आई. आर. ई. सी. एल. के नाम से जाना जाता था) और एस. एच. आई. सी. एल. तब तक धन जुटाने के लिए प्रतिभूति बाजार का उपयोग नहीं

करेंगे जब तक कि उपरोक्त भुगतान एस. ई. बी. आई. की संतुष्टि के लिए नहीं किए जाते।

2. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, सहारा ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) के समक्ष एक अपील दायर की, जो एस. ई. बी. आई. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत था, और एस. ई. बी. आई. द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, सहारा को छह सप्ताह की अवधि के भीतर निवेशकों से एकत्र की गई राशि को वापस करने का निर्देश दिया।

3. इसके बाद सहाराओं ने उपरोक्त आदेशों के खिलाफ अपील संख्या 9831 और 9833 /2011 दायर की, जिसमें इस न्यायालय ने 28 नवंबर, 2011 के एक आदेश द्वारा धनवापसी करने की अवधि 9 जनवरी, 2012 तक बढ़ा दी, लेकिन अंत में 31 प्रतिशत अगस्त, 2012 के आदेश द्वारा अपीलों का निपटारा कर दिया। इस न्यायालय ने ऐसा करते हुए एस. ई. बी. आई. और एस. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया और सहारों को निर्देश दिया कि वे अपने आर. एच. पी. द्वारा से एकत्र की गई राशि को तीन महीने की अवधि के भीतर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ एस. ई. बी. आई. में जमा करें। जमा की गई राशि को ब्याज अर्जित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश करने का निर्देश दिया गया था। सहारों को यह स्थापित करने के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था कि क्या उन्होंने उन निवेशकों को कोई राशि वापस की थी जिन्होंने विचाराधीन आरएचपी द्वारा से सदस्यता ली थी। एस. ई. बी. एल. को इस प्रकार प्रस्तुत किए गए विवरणों की शुद्धता की जांच करनी थी। सहारा द्वारा राशि की वापसी को साबित करने में विफलता को इस निष्कर्ष को जन्म देना पड़ा कि सहारा ने वास्तविक और वास्तविक ग्राहकों को राशि वापस नहीं की थी जैसा कि एस. ई. बी. आई. द्वारा निर्देशित किया गया था।

4. यह सामान्य आधार है कि इस न्यायालय द्वारा 31 प्रतिशत अगस्त, 2012 के अपने आदेश द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इसके बजाय अपील सं.221/2012 को सहाराओं द्वारा एस. ए. टी. के समक्ष प्राथमिकता दी गई थी जिसे न्यायाधिकरण ने समयपूर्व बताते हुए खारिज कर दिया था। यह बर्खास्तगी सहारों द्वारा के सीए सं संख्या 8643/2012 में की गई थी, जिसे इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 5 दिसंबर, 2012 के एक आदेश द्वारा निम्नलिखित अन्य निर्देशों के साथ निपटाया गया थाः

> "(एल) अपीलार्थी तुरंत 5120 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए मांग मसौदे, जो आपने न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं, को एस. ई. बी. आई. को सौंप देंगे और 31 अगस्त, 2012 के आदेश के अनुसार शेष राशि, अर्थात् 17,400 करोड़ रुपये और पूरी राशि जमा करेंगे। एस. ई. बी. के साथ दो किश्तों में प्रति वर्ष 15 प्रतिशत के ब्याज के साथ ऊपर उल्लिखित राशि भी शामिल है। 10, 000 करोड़ रुपये की पहली किस्त जनवरी, 2013 के पहले सप्ताह के भीतर एस. ई. बी. आई. के पास जमा की जाएगी।शेष राशि, ब्याज के साथ, जैसा कि गणना की गई है, फरवरी, 2013 के पहले सप्ताह के भीतर जमा की जाएगी। जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है, किसी भी व्यक्ति को किए गए धनवापसी के समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने का समय 15 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। उक्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर, एस. ई. बी. आई. 31 अगस्त, 2012 को पारित आदेश में निहित निर्देशों को लागू करेगा।निर्धारित अवधि के भीतर उक्त दस्तावेजों को जमा करने में चूक होने पर, या दोनों किश्तों में से किसी एक को जमा करने में चूक होने की स्थिति में, 31 अगस्त,

2012 के उपरोक्त आदेश के पैराग्राफ 10 में निहित निर्देश तुरंत लागू हो जाएंगे और एस. ई. बी. आई. बकाया राशि की वसूली के लिए संपत्तियों की कुर्की और बिक्री, बैंक खातों को फ्रीज करने आदि सहित सभी कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।"

5. उपरोक्त के अनुसार, सहारा ने एस. ई. बी. आई. के पास रू .5120-करोड़ जमा किए लेकिन शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहे। उस पर देय ब्याज को छोड़कर शेष राशि रू.12280-करोड़ के आसपास है, इसके बाद एस. ई. बी. आई. ने इस न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानकर्ताओं के खिलाफ अवमानना याचिका सं. 412 और 413 और 2013 की अवमानना याचिका 260/2013 दायर की। इन अवमानना याचिकाओं में समय-समय पर विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं, और जो हमारे उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं, उन्हें उचित स्तर पर इसके बाद भेजा जाएगा। जिन आवेदनों (आई. ए.) पर हम इस आदेश में विचार कर रहे हैं, वे इन अवमानना याचिकाओं में दायर किए गए हैं और पारित किए गए पहले के आदेशों से उत्पन्न होते हैं।

6. इस स्तर पर यह इंगित करना उचित है कि उपरोक्त अवमानना याचिकाओं की कार्यवाही के दौरान पक्षकारों द्वारा कुछ प्रस्तावों पर विचार किया गया प्रतीत होता है। इस न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन, लेकिन इस तरह के सभी प्रस्ताव असंतोषजनक पाए गए, अंततः इस न्यायालय के समक्ष श्री सुब्रत राय सहारा को पेश करने के लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। सहारा के तीन अन्य निदेशकों को भी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था।

7. 4 मार्च, 2014 को जब अवमानकर्ता इस अदालत के समक्ष पेश हुए, तो उनमें से एक हिरासत में, इस अदालत ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि अदालत द्वारा

31 अगस्त, 2012 और 5 दिसंबर, 2012 के अपने आदेश द्वारा जारी किए गए निर्देश और 2012 के सीए सं.8643 और आइ.ए. सं. 67/2013 में 25 फरवरी, 2013 को जारी किए गए निर्देशों का, अवमानकर्ताओं को ऐसा करने के पर्याप्त अवसरों के बावजूद, पालन नहीं किया गया था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अवमानकर्ताओं ने एस. ई. बी., उच्च न्यायालय और यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष भी कार्यवाही में देरी करने के लिए विलंबकारी रणनीति अपनाई थी। यह भी पाया गया कि इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए कोई स्वीकार्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसने इस न्यायालय के लिए चार अवमानकों में से तीन को न्यायिक हिरासत में देने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अवमानकर्ता, उक्त आदेश के बाद से, दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

8. उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि पारित आदेशों के अनुसार, लगभग 33,000/- करोड़ की एक बड़ी राशि अभी जमा की जानी है। यह भी स्पष्ट है कि इस राशि को जमा करने की समय सीमा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सहारों द्वारा भुगतान करने के लिए विभिन्न प्रस्ताव दिए गए हैं लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है।पहले पारित आदेशों की अवधि से, यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इन प्रस्तावों ने विश्वास को प्रेरित नहीं किया। इस पृष्ठभूमि में जब मामला 26 मार्च, 2014 को फिर से आया और अवमानकर्ताओं ने उन्हें जमानत देने पर जोर दिया, तो इस अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए एक सशर्त आदेश पारित किया। अवमानकर्ता; शर्त यह है कि वे रू.10,000/- करोड़ जमा करते हैं। इसमें से 5,000 करोड़ रुपये की राशि इस न्यायालय के समक्ष नकद में जमा करनी थी, जबकि शेष राशि रू.5000-करोड़ की राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित किया जाना था, जिसे एसईबीआई के पक्ष में प्रस्तुत किया गया था। उन शर्तों का पालन करने पर अवमानकर्ताओं को हिरासत से रिहा करने और उनके

द्वारा जमा की गई राशि को एस. ई. बी. आई. को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था। चूँकि हम सीधे तौर पर इस आदेश से संबंधित हैं, इसलिए हम भी इसे निकाल सकते हैंः

> "हम द्वारा 25.3.2014 पर दायर किए गए नए प्रस्ताव को देखा है। इसद्वारा से हमारे दिनांकित 31.8.2012 के आदेश या सिविल अपील सं.8643/2012 में 5.12.2012 पर इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित आदेश और सिविल अपील सं.9813/2011 में आई ए नंबर 67 पर आई ए नंबर 5 के साथ की सिविल अपील सं.9833/2013 में हम अवमानकों को अंतरिम जमानत देने के लिए इच्छुक हैं, जिन्हें हमारे दिनांकित 4.3.2014 के आदेश के आधार पर हिरासत में लिया गया है, इस शर्त पर कि वे रु 10, 000 करोड़-जिसमें से रु 5,000 करोड़ रुपये इस न्यायालय के समक्ष जमा किए जाएंगे और शेष राशि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी दी जाएगी। और इस न्यायालय के समक्ष जमा किया जाए।
>
> अनुपालन पर अवमानकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए और जमा की गई राशि को एस. ई. बी. आई. को जारी किया जाए।
>
> हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश अवमानकर्ताओं को शेष राशि को और बढ़ाने में सुविधा प्रदान करने के लिए पारित किया गया है ताकि ऊपर उल्लिखित न्यायालय के आदेशों का पालन किया जा सके।"

9. उपरोक्त निर्देशों का पालन करने के बजाय श्री डी. सुब्रत राय सहारा ने रिट याचिका (सी. आर. एल.) सं. 57/2014 दायर की। इस न्यायालय के दिनांक 4 के

आदेश की वैधता को चुनौती देता है। मार्च, 2014 इस आधार पर कि यह अमान्य था और कानून की नजरों में महत्वहीन था। याचिकाकर्ता श्री सुब्रत राय सहारा को हिरासत में निरंतर कैद रखने की घोषणा अवैध थी और बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट और याचिकाकर्ता को हिरासत से रिहा करने के निर्देश के लिए अनुरोध किया गया था। उक्त रिट याचिका की सुनवाई माननीय के. एस. राधाकृष्णन और जे. एस. खेहर, जे. जे. की पीठ ने की और 6 मई, 2014 के विस्तृत फैसले के माध्यम से इसे खारिज कर दिया गया।

10. इस मामले की अन्यथा लंबी यात्रा को संक्षेप में पार करने के बाद, हम आई. ए. पर वापस लौटते हैं जो तत्काल आदेश की विषय वस्तु हैं। वर्तमान आई. ए. अवमानना याचिका (सी) सं.412 और 413/2012 की और 2013 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 260/2013 अवमानकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थना की हैः

> "(क) इस माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाएं-बैंक खातों/जमा/डीमैट खातों/अनुलग्नक-ए में उल्लिखित प्रतिभूतियों की बिक्री के संचालन के संबंध में अपने दिनांकित 21.11.2013 के आदेश और 13.2.2013 के एसईबीआई के आदेश के माध्यम से;
>
> (ख) संलग्नक ख में उल्लिखित चल और अचल संपत्तियों के संबंध में इस माननीय न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित आदेश और दिनांकित एस. ई. बी.आई के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को इस शर्त पर हटा दें कि उनकी शुद्ध आय (लागत और करों के बाद) का उपयोग इस माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित भुगतान के लिए विशेष रूप से किया जाए।

(ग) ऐसा आगे या अन्य आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।"

11. न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन ने पद छोड़ने के बाद और न्यायाधीश जे. एस. खेहर ने मामले की अगली सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद, आवेदनों को 19 मई, 2014 को तत्काल सुनवाई के लिए हमारे सामने सूचीबद्ध किया गया था, जब उनकी भाग में सुना की गई और 29 मई, 2014 को जारी रखने के लिए आने का निर्देश दिया गया।

12. अवमानकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए डॉ. राजीव धवन ने हमारे सामने तीन बार निवेदन किया। सबसे पहले, उन्होंने तर्क दिया कि उक्त आदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत देने के लिए इस न्यायालय द्वारा 26 मार्च, 2014 को पारित आदेश को संशोधित किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें निर्धारित शर्तें न केवल कठिन थीं, बल्कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उनका पालन करने में असमर्थ थीं।वैकल्पिक रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के लिए सहारा समूह की कंपनियों द्वारा रखी गई अचल संपत्तियों की कई वस्तुओं की बिक्री की आवश्यकता होगी, जिनकी बिक्री को केवल तभी अंतिम रूप दिया जा सकता है जब अवमानकर्ताओं को हिरासत से बढ़ा दिया जाए ताकि वे बिक्री लेनदेन पर बातचीत कर सकें। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संपत्तियों की सीमा और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिन्हें बेचा जाना है और साथ ही इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए जमा करने का आदेश दिया गया है, यह बहुत मुश्किल है, यदि असंभव नहीं है, जब तक कि अवमानकर्ताओं को जेल से बाहर नहीं किया जाता है और अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। डॉ. धवन ने आगे तर्क दिया कि 'सहारों' द्वारा धारित चल और अचल संपत्तियों की बिक्री के

खिलाफ प्रतिबंध आदेशों ने उनके लिए अनुपालन की व्यवस्था करना असंभव बना दिया है जब तक कि इस अदालत के 21 प्रतिशत नवंबर, 2013 के आदेश द्वारा इस तरह की बिक्री और हस्तांतरण पर लगाए गए प्रतिबंध और 13 फरवरी, 2013 को SEBI द्वारा पारित प्रतिबंध को हटा नहीं दिया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही अवमानकर्ताओं को 26 मार्च, 2014 को इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं होने तक जमानत पर रिहा नहीं किया गया था, लेकिन प्रतिबंध आदेश अवमानकर्ताओं को इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक धन जुटाने से रोकेंगे।उन्होंने आग्रह किया कि वर्तमान में कई बैंक खातों में पड़ी और/या बैंकों और कंपनियों के साथ एफ. डी., बांड और प्रतिभूतियों आदि के रूप में निवेश की गई कुल राशि लगभग 1 करोड़ रुपये है। डॉ. धवन द्वारा प्रस्तुत किए गए ध्यान दें में सहारा द्वारा उपलब्ध राशि का व्यापक विवरण नीचे दिया गया हैः

लगभग का विवरण सहारों को प्रतिबंध हटाने के 5 कार्य दिवसों के भीतर उस पर उपार्जित ब्याज के साथ 2500 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा (पृष्ठ 39 -54)

क) सावधि जमा	1688.74 करोड़
ख) बचत खाता	464.44 करोड़
ग) चालू खाता	18.45 करोड़
क) प्रतिभूति और बांड	142.86 करोड़
ख) सरकारी बॉन्ड	72.33 करोड़
ग) बैंक/पीएसयू बॉन्ड	34.85 करोड़
	2421.67 करोड़

कुल लगभग 2500 करोड़ रुपये उस पर अर्जित ब्याज के साथ

13. डॉ. धवन ने तर्क दिया कि एफ. डी. को भुनाने, बॉन्ड और प्रतिभूतियों की बिक्री और हस्तांतरण से अवमानकर्ताओं को रू.2500-करोड़ जमा करने के निर्देशों का आंशिक रूप से पालन करने में मदद मिलेगी। जमा के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटानी होगी जो केवल नौ अलग-अलग शहरों में स्थित अचल संपत्तियों की बिक्री से ही संभव होगी, जिनका विवरण डॉ. धवन द्वारा ऐसी संपत्तियों के अनुमानित मूल्य के साथ एक बयान के रूप में दायर किया गया था जो निम्नानुसार हैः

क्रम संख्या	गुण	मूल्यांकन मूल्यांकन रिपोर्ट (रु. करोड़ में)	खंड 1 का पृष्ठ संख्या
1.	पुणे	575	60-76 @73
2.	अहमदाबाद	470	81-98 @94
3.	अमृतसर	153.75	99-127 @111
4.	चौमा	1430	128-148 @140
5.	वसई	1169.72	143-160 @149
6.	अजमेर	160	161-175 @167
7.	भावनगर	103	176-191 @168
8.	जोधपुर	112	192-208 @204
9.	भोपाल	125	209-224 222
	कुल	4298.47	

14. यह प्रस्तुत किया गया था कि संपत्ति की उपरोक्त वस्तुओं की बिक्री भी अंतरिम जमानत देने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकती है, जिससे सहाराओं के लिए देश के बाहर स्थित होटल संपत्तियों की तीन अन्य वस्तुओं को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। ग्रॉसवेनर हाउस नामक इनमें से एक होटल लंदन में स्थित है जबकि शेष दो होटल न्यूयॉर्क (यू. एस. ए.) में हैं।यह आग्रह किया गया कि मार्जिन राशि जुटाने के लिए संपत्ति की उक्त तीन वस्तुओं को भी बेचे जाने की आवश्यकता है, जिस पर संबंधित बैंक जोर देते हैं ताकि वे बैंक गारंटी जारी कर सकें। यह प्रस्तुत किया गया था कि अवमानकर्ता एंबी वैली की संपत्तियों को गिरवी रखने का प्रस्ताव करते हैं, जिसका विवरण संलग्नक बी सं.101-103, अवमानकर्ताओं को किसी भी सेवा के लिए धन की आवश्यकता होगी। बैंक/बैंकों के साथ की गई वित्तीय व्यवस्था।यह भी तर्क दिया गया कि अवमानकर्ताओं के अनुमान के अनुसार, लंदन और न्यूयॉर्क में स्थित संपत्तियों से अवमानकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी, जिसका उपयोग बैंक गारंटी प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्जिन राशि के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किया जा सकता है। इन तीन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य अवमानकर्ताओं द्वारा निम्नानुसार इंगित किया गया हैः

अतटीय संपतियों का स्वामीत्व रखने वाली संस्थाओं के शेयर	मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मूल्य	आपेक्षित बिक्री मूल्य	तत्काल अग्रिम आपेक्षित	पृष्ठ सं
ग्रोसवेनर हाउस,	जी. बी. पी.	जी. बी. पी.	यू. एस. डी.	667-वाल्युम

लंदन	516,000,000 रू 50,929,200,000	645,000,000 रु 63,661,500,000	50,000,000 रू 2,900,000,000	III
प्लाजा होटल,न्यूयॉर्क	यू. एस. डी. 592,000,000 रु 34,336,000,000	यू. एस. डी .635,000,000 रु. 36,830,000,000	यू. एस. डी 50,000,000 रु. 2,900,000,000	415-वाल्युम III
ड्रीम्स डाउनटाउन होटल,न्यूयॉर्क	यू. एस. डी. 252,000,600 रु 14,616,000,000	यू. एस. डी. 252,000,600 रु 14,616,000,	यू. एस. डी. 50,000,000	231-वाल्युम III
कुल		रु. 115,107,500,000	यू. एस. डी 150,000,000 रु. 8,700,000,000	

भारत में सहारा के लिए शुद्ध यथार्थवादी समता का मूल्य		रुपये 50,366,156,000		

15. प्रत्यर्थी-एस. ई. बी. आई. की ओर से श्री वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि उन्हें एफ. डी. प्राप्तियों और अन्य प्रतिभूतियों और बैंडों आदि के भुनाने पर कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि ऐसे एफ. डी. आर., प्रतिभूतियों और बांडों के परिपक्वता मूल्य और बिक्री पर विचार को एस. ई. बी. आई. के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया जाए। बैंक ऑफ इंडिया, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स शाखा, मुंबई के साथ रिफंड खाता सं.012210110003740 वाला एसईबीआई सहारा ऊपर वर्णित नौ अलग-अलग शहरों में स्थित संपत्तियों की बिक्री या बंधक के संबंध में, श्री वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि इस तरह की बिक्री और हस्तांतरण के लिए उचित सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, श्री वेणुगोपाल ने इस संबंध में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का सुझाव दियाः

(i) मूल्यांकन, खरीदार (ओं) और बिक्री की शर्तों का विवरण साथ में आशय पत्र (ओं) के साथ इस माननीय न्यायालय को अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया जाए;

(ii) खरीदार को सहारा समूह की संस्थाओं/निदेशक आदि से संबंधित पक्ष/पक्ष नहीं होना चाहिए और इस आशय का शपथ पत्र इस माननीय न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए।

(iii) बिक्री आय खरीदार द्वारा सीधे एस. ई. बी. आई. के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा की जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स शाखा, मुंबई के साथ वाला

"एसईबीआई -सहारा रिफंड खाता सं.012210110003740 और

(iv) उपरोक्त बैंक खाते में बिक्री आय की प्राप्ति के बाद ही खरीदार को एस. ई. बी. आई. द्वारा स्वामित्व विलेखों का वास्तविक विमोचन किया जाएगा।

16. इस आशय का निर्देश भी दिया गया था कि संपत्तियों की बिक्री उस क्षेत्र के लिए निर्धारित सर्कल दरों से कम कीमत पर नहीं होगी जहां संपत्तियां स्थित हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में सुझाव दिया गया।श्री वेणुगोपाल द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि जब तक देश के बाहर स्थित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उचित और उचित है, तब तक एस. ई. बी. आई. को इसकी बिक्री पर कोई आपत्ति नहीं थी ताकि अवमानकर्ता इस न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिए आवश्यक धन जुटाने में सक्षम हो सकें।

17. हमने बार में की गई प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है, बार में की गई प्रस्तुतियों से यह स्पष्ट है कि इन आई. ए. के दो अंग हैंःसबसे पहले, अवमानकर्ता राशि जमा करने के संबंध में इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए बैंक जमा और अचल संपत्तियों पर प्रतिबंध आदेशों में छूट चाहते हैं।प्रार्थना का वह भाग कोई कठिनाई पैदा नहीं करता है, क्योंकि यह इस न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सहायता करता है। प्रार्थनाओं का दूसरा समूह जमानत देने या जेल की शर्तों में ढील देने के लिए है। यहाँ हम अपने आरक्षण हम उक्त आदेश में निर्धारित शर्तों पर अवमानकर्ताओं को अंतरिम जमानत देने वाले 26 प्रतिशत मार्च, 2014 के आदेश में संशोधन करने के इच्छुक नहीं हैं। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस पृष्ठभूमि में अवमानकर्ता जेल के प्रति प्रतिबद्ध हुए और अदालत द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि उन्होंने सभी प्रारंभिक चरणों में विलंबकारी रणनीति अपनाने की कोशिश की है और अदालत द्वारा पारित आदेशों का पालन करने से बचा है, हमारे

विचार में उन शर्तों में किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है जिन पर अवमानकर्ताओं को रिहा किया जा सकता है।डॉ. धवन ने वैकल्पिक रूप से अनुरोध किया कि अवमानना करने वालों को तिहाड़ जेल से जेल में रखने के लिए एक अतिथि गृह में स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि वे इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए आवश्यक निर्णय ले सकें। श्री वेणुगोपाल ने इस अनुरोध का विरोध किया था, जिनके अनुसार अतीत में कई सुनवाई में बार-बार किए गए इसी तरह के अनुरोधों को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, हालांकि इससे इनकार करने वाला कोई विशिष्ट आदेश दर्ज नहीं किया गया था।उस निवेदन के समर्थन में, 20 मई, 2014 को उनके द्वारा दायर आई. ए. एस. संख्या 2 से 4 में आवेदक द्वारा किए गए कथन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, जो कथन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वास्तव में अतीत में भी इसी तरह की प्रार्थनाएं की गई थीं।

18. इस तथ्य के अलावा कि अब की गई प्रार्थना अतीत में की गई इसी तरह की प्रार्थनाओं की पुनरावृत्ति है, जिसने मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के साथ कोई बर्फ नहीं काटा है, हम वर्तमान मामले में सामान्य पाठ्यक्रम से हटने का कोई कारण नहीं देखते हैं।पीठ ने अवमानकर्ताओं के आचरण सहित परिचर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित और उचित विचार के बाद एक सशर्त जमानत आदेश पारित किया है। आदेश को केवल बहुत ही बाध्यकारी परिस्थितियों में ही संशोधित किया जा सकता है। आवेदकों द्वारा दिया गया एकमात्र कारण यह है कि अवमानकर्ताओं की अंतरिम रिहाई या अतिथि गृह में स्थानांतरण उन्हें संपत्तियों का तेजी से निपटान करने में सक्षम बनाएगा और उन्हें आवश्यक बैंक गारंटी की व्यवस्था करने में सक्षम बनाएगा। हम ऐसा नहीं सोचते। उल्लेखनीय है कि जमा की जाने वाली कुल राशि है - रु. 33000/- से रु 35000/- करोड़ अपनी प्रामाणिकता दिखाने के लिए, अवमानकर्ताओं को जमानत की शर्त के रूप में उस राशि के एक तिहाई से कम राशि जमा करने का

निर्देश दिया गया है। आखिरकार, जब आदेश के इस हिस्से का पालन किया जाता है और अवमानकर्ताओं को मुक्त कर दिया जाता है, तो उन्हें शेष राशि जमा करने की व्यवस्था करनी होगी, जो फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह अवमानकर्ताओं का मामला नहीं है कि वे या उनमें से कोई भी किसी भी चिकित्सा स्थिति से पीड़ित है जो अस्पताल में भर्ती होने या किसी भी बीमारी से उबरने के लिए अनुकूल वातावरण की मांग करता है। यह न्यायालय पहले ही उन लोगों से मिलने की अनुमति देने के निर्देश जारी कर चुका है जिन्हें जेल में अवमानना करने वालों से मिलने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था वर्तमान में अपर्याप्त नहीं पाया गया है ताकि किसी भी परिवर्तन का आह्वान किया जा सके।

19. तदनुसार, आदेश के संशोधन के लिए प्रार्थना विफल हो जाती है।

20. तथापि, हम डॉ. धवन द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन में काफी योग्यता पाते हैं कि सहारा समूह की कंपनियों द्वारा चल और अचल संपत्तियों के हस्तांतरण और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाले इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रतिबंध आदेश का प्रभाव अवमानकर्ताओं को इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने से रोकने का है, जिसमें उन्हें 5,000/- करोड़ रुपये की समान राशि के लिए बैंक गारंटी के अलावा 5,000/- करोड़ रुपये नकद जमा करने की आवश्यकता है। हालांकि यह सच है कि अवमानकर्ता इस न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के लिए जेल जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्हें उक्त निर्देशों या उन शर्तों का पालन करने के लिए कदम उठाने से कुछ भी नहीं रोकना चाहिए जिनके अधीन उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है।अवमानकर्ताओं और उनके द्वारा प्रवर्तित कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के खिलाफ प्रतिबंध का ऐसा करने का सटीक प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, सवाल यह है कि प्रतिबंध के आदेशों को किस हद तक संशोधित किया जाना चाहिए।यह पहलू इस तथ्य के कारण महत्वपूर्ण है कि सहारों को अंततः एक पर्याप्त राशि जमा

करने की आवश्यकता है जो वर्तमान अनुमान के अनुसार रु 30, 000 से रु 35,000 करोड़ मूल राशि पर उपार्जित ब्याज सहित ऐसी परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य से कम कीमत पर मूल्यवान संपत्तियों की बिक्री जमाकर्ताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपने अक्षर और भावना में विफल करने के लिए बाध्य है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि श्री वेणुगोपाल के अनुसार, एस. ई. बी. आई. संपत्तियों का मूल्यांकन करने या उनकी बिक्री और हस्तांतरण को संसाधित करने में असमर्थ है। इसी पृष्ठभूमि में हमने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता डॉ. धवन को संकेत दिया था कि प्रतिबंध आदेशों को पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता है और यह कि सहरों को ऐसी संपत्तियों की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव के साथ आगे आना चाहिए जो 5,000/- करोड़ रुपये 5.000-इसके अलावा नकद जमा करने के संबंध में इस न्यायालय के अंतरिम जमानत निर्देश का पालन करने के लिए पर्याप्त थे। डॉ. धवन ने उस अवलोकन के अनुसार देश के नौ अलग-अलग शहरों में स्थित संपत्तियों की केवल नौ वस्तुओं को बेचने/स्थानांतरित करने की अनुमति के लिए अपनी प्रार्थना को सीमित कर दिया है और बयान में ऐसी संपत्ति के अनुमानित मूल्य का खुलासा किया है जो हमने ऊपर निकाला है। डॉ.:धवन ने निर्देश पर एक बयान दिया कि हालांकि उनके द्वारा दायर ध्यान दें में उन शहरों में स्थित संपत्तियों का विवरण दिए बिना नौ अलग-अलग शहरों के नामों का उल्लेख किया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि ध्यान दें में उल्लिखित संपत्तियों की संख्या केवल नौ है और अधिक नहीं है।

21. सहारा समूह की कंपनियों द्वारा धारित संपत्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, ध्यान दें में उल्लिखित और ऊपर निकाले गए नौ शहरों में स्थित संपत्तियों की नौ वस्तुओं की बिक्री और/या बंधक का हस्तांतरण, हमारी राय में, अवमानकर्ताओं को इस न्यायालय के 26 मार्च, 2014 के निर्देशों का पालन करने में

सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित आदेशने के लिए कि बिक्री मूल्य उचित और उचित है, हमें यह स्पष्ट आदेशने की आवश्यकता है कि संपत्ति की कोई भी वस्तु उस क्षेत्र के लिए निर्धारित संपत्तियों के वृत्त मूल्य से कम मूल्य पर नहीं बेची जाएगी जहां ऐसी संपत्ति स्थित है।

22. जहां तक लंदन और न्यूयॉर्क में स्थित संपत्तियों का संबंध है, हमने 29 मई, 2014 को पारित एक अंतर्वर्ती आदेश द्वारा अवमानकर्ताओं को उक्त संपत्तियों की बिक्री की अनुमति देने के लिए आवश्यक कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। माँगी गई जानकारी में बैंक ऑफ चाइना से अनुमति/अनुमोदन शामिल है जिसके साथ उक्त संपत्तियाँ गिरवी रखी गई हैं और उक्त बैंक से उधार लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सहारा द्वारा रखे गए शेयर शामिल हैं। हमने सहारों को बैंक ऑफ चाइना से उक्त संपत्तियों की पुष्टि के लिए ऋण लेनदेन के लिए बकाया राशि प्राप्त करने का भी निर्देश दिया है ताकि हमें इस बात की स्पष्ट तस्वीर मिल सके कि उक्त संपत्तियों के खिलाफ दायित्व की सीमा का भुगतान किया जाना बाकी है। यह तथ्य कि तीन परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट बैंक ऑफ चाइना के कहने पर तैयार की गई थी, बैंक ऑफ चाइना द्वारा भी सत्यापित और पुष्टि की जानी चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि विचाराधीन परिसंपत्तियों की किसी भी बिक्री की अनुमति उस कीमत से कम कीमत पर नहीं दी जा सकती है जिस पर उक्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उन मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया गया है जिन्हें प्रतिष्ठित मूल्यांकनकर्ता कहा जाता है।देश के बाहर परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में निर्देश, इसलिए, जानकारी के धूमिल होने और तथ्यों के सत्यापन की प्रतीक्षा कर सकते हैं।

23. परिणामस्वरूप हम इनका निपटारा करते हैं जैसा कि निम्नलिखित निर्देशों के साथ हैः

(i) अवमानकर्ताओं को अंतरिम जमानत देने के हमारे 26 मार्च, 2014 के आदेश में निर्धारित शर्तों में संशोधन की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है और उस हद तक खारिज कर दिया गया है।

(ii) अवमानकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर उनकी रिहाई के लिए इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने तक निरंतर हिरासत और निरोध के लिए एक अतिथि गृह में स्थानांतरित करने की प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया जाता जैसा कि उस हद तक खारिज कर दिया गया।

(iii) सहारा द्वारा धारित चल और अचल संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए इस न्यायालय द्वारा 21 प्रतिशत नवंबर, 2013 को पारित और 13 फरवरी, 2013 को एस. ई. बी. आई. द्वारा पारित आदेशों को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया गया है।

(ए) एफडी, बांड और प्रतिभूतियां सहारा कंपनियों के समूह द्वारा धारित को भुनाया जा सकता है उसके धारक इस शर्त के अधीन हैं कि ऐसी एफडी की परिपक्वता मूल्य/बिक्री पर विचार, बांड और प्रतिभूतियां डी में जमा की जाएंगी सेबी के निर्दिष्ट बैंक खाते का उल्लेख किया गया है इस आदेश के पहले भाग और विवरण में ऐसे परिपक्वता मूल्य और बिक्री पर विचार दायर किए जाने वाले हलफनामे पर इस न्यायालय को एफडी, बांड और प्रतिभूतियों को भुनाने, बेचने और/या करने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर तबादला प्रस्तुत किया गया।

(ख) 9 अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित सहारा समूह की कंपनियों के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियाँ डॉ. धवन द्वारा दायर किए गए और इस आदेश के मुख्य भाग में निकाले गए ध्यान दें में उल्लिखित शहर 2500/- करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य के साथ उन कंपनियों/अन्य संस्थाओं द्वारा बेचे जाने की अनुमति है जिनके नाम पर ऐसी

संपत्तियां इस शर्त के अधीन हैं कि ऐसी बिक्री इस न्यायालय के समक्ष दायर विवरण में इंगित अनुमानित मूल्य या उस क्षेत्र के लिए निर्धारित सर्कल दरों से कम मूल्य के लिए नहीं है जिसमें ऐसी संपत्तियां स्थित हैं।विक्रेता इस न्यायालय को बेची गई संपत्तियों के मूल्यांकन और बिक्री की शर्तों का विवरण इस घोषणा के साथ प्रस्तुत करेगा कि खरीदार सहारों से संबंधित पक्ष नहीं हैं।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बिक्री प्रतिफल जमा करने पर संपत्ति के स्वामित्व विलेख खरीदार (ओं) के पक्ष में एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी किए जाएंगे।

(ग) कम लेन-देन लागत वाली संपत्तियों की बिक्री पर विचार और उस पर वैधानिक बकाया राशि को एस. ई. बी. आई. के पास इस हद तक जमा किया जाएगा कि एफ. डी., बांड और प्रतिभूतियों आदि के परिपक्वता मूल्य और बिक्री आय सहित कुल 5,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए आवश्यक है, जिन्हें उपरोक्त निर्देश (ii) (ए) के संदर्भ में भुनाने और बेचने की अनुमति दी गई है। बिक्री प्रतिफल की शेष/अतिरिक्त राशि सहारा द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले जाने वाले एक अलग खाते में जमा की जाएगी जो इस न्यायालय के आगे के आदेशों के अधीन रहेगी।

(घ) सहारों को एम्बी में स्थित अपनी अचल संपत्तियों को चार्ज करने की भी अनुमति है। घाटी (पुणे), जिनके बकाए संलग्नक बी में आई. ए. सं101-103 में दिए गए हैं, 5,000/- करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने के उद्देश्य से और/या 5,000/- करोड़ रुपये जमा करने के लिए, यदि उपरोक्त (iii) (ए) और (iii) (बी) के संदर्भ में अनुमत नकदीकरण और बिक्री के बावजूद कोई कमी है।

(ङ) 26 मार्च, 2014 के आदेशों में संशोधन करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि बैंक एक करोड़ रुपये की गारंटी देता है। 5, 000/- करोड़ रुपये केवल राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक से दिए जाएंगे। सहकारी बैंक गारंटी पर्याप्त नहीं होगी।

(iv) जहां तक देश के बाहर स्थित तीन संपत्तियों की बिक्री का संबंध है, सवाल को 29 मई, 2014 के हमारे आदेश के संदर्भ में सहारा द्वारा आवश्यक दस्तावेज/जानकारी उपलब्ध कराने के बाद निर्धारित करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।

(v) इन कार्यवाहियों में निर्धारण के लिए आने वाले मुद्दों के महत्व और इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जिसे इन कार्यवाहियों में लागू करने की मांग की गई थी, तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित किया गया था, हम इन कार्यवाहियों को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित की जाने वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करते हैं।

(vi) हमारा आगे यह विचार है कि इन कार्यवाहियों की प्रकृति और इसमें शामिल हितधारकों को ध्यान में रखते हुए, हमें एक न्यायालय मित्र नियुक्त करने की आवश्यकता है। तदनुसार हम वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एफ. एस. नरीमन से न्यायालय मित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध करते हैं। श्री नरीमन इस मामले में उन्हें जानकारी देने के लिए अपनी पसंद के दो कनिष्ठों को शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(vii) हम निर्देश देते हैं कि न्यायालय मित्र प्रति सुनवाई रुपये 1,10,000 की दर से शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जबकि उसकी सहायता करने वाले कनिष्ठों को रुपये का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक सुनवाई के लिए प्रति व्यक्ति 10,000/- इस प्रकार देय राशि का भुगतान एस. ई. बी. आई. द्वारा डेबिट टू अकाउंट सहारा द्वारा किया जाएगा।

निधि जैन आई. ए. का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।